

From : vidhyaalmora@gmail.com

Tue, Jan 09, 2024 06:33 PM

Subject : ideas about budget **To :** Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

Sir

In fy 2024-25 the land selling to another state person must be called off or bained. Our rural state persons are not able to make their own domicile certificate in uttarakhand due to their lack of knowledge because they sold their entire share of land to outsiders and now they are called landless people in uttarakhand. Beside it, our government should provide them with a minimum percentage loan by which they make their own home stay and make money from outsiders and take a part in our state revenue. It is an long time process but land ot our state is not acquired by an outsider by this process.

With all hopes

(Pankaj Sah)

Karkhana BAzar Almora

263601

9568793349

Email

Budget Department Gov. of Uttarakhand

Suggestion regarding up comming budget

From : ArvindSingh
<ar.singh.ukp@uttarakhandpolice.uk.gov.in>

Tue, Jan 02, 2024 03:56 PM



Subject : Suggestion regarding up comming budget

To : Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

महोदय/महोदया,
आप अवगत ही हैं कि हम ग्रीन इकॉनोमी की ओर बढ़ रहे हैं और पर्यावरण के प्रति आज पूरा विश्व चिंतित होने के साथ-साथ इसके संरक्षण हेतु प्रयासरत है। मा0 प्रधानमंत्री जी भी पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थक हैं। उत्तराखण्ड राज्य एक पर्यटक राज्य है तथा इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। इकोटूरिज्म पर विशेष फोकस किया जाना अनिवार्य है। अतः मेरा सुझाव यही है कि राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)-2024-25 में पर्यावरण संरक्षण, इकोटूरिज्म, वनीकरण, हरित ऊर्जा जैसे पर्यावरणीय मित्र आर्थिकी पर विशेष ध्यान दिया जाय। साथ ही इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा। प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री सुन्दरलाल बहुगुणा जी का भी यही विचार है कि **Ecology is permanent Economy**. इस विचार/संकल्पना को आधार मानकर हम अपने राज्य में पर्यावरणीय अनुकूल अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।

धन्यवाद

अरविन्द सिंह
उप निरीक्षक
उत्तराखण्ड पुलिस
मो0 9411747960



विषय - आगामी बजट में उत्तराखंड की समस्त hwc में कार्यरत योग अनुदेशकों को सम्मान जनक मानदेय, उनको भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन व स्थाई नियुक्ति के सन्दर्भ में निवेदन हेतु।

From : anilraturi24@gmail.com

Thu, Dec 28, 2023 07:42 PM

Subject : विषय - आगामी बजट में उत्तराखंड की समस्त hwc में कार्यरत योग अनुदेशकों को सम्मान जनक मानदेय, उनको भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन व स्थाई नियुक्ति के सन्दर्भ में निवेदन हेतु।

To : Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

महोदय आपको विदित ही है कि प्रदेश के आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में आयुष्मान भारत मिशन के तहत समस्त hwc में योग अनुदेशक 250 रु दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत हैं, आप भली भांति जानते हैं कि यह योग अनुदेशक के साथ भेदभाव व उनका शोषण है।

इस महंगाई के दौर में दैनिक 250 रु में आपने परिवार का भरण पोषण कैसे होता होगा यह नीति नियंत्रणों को सोचना ही पड़ेगा।

महोदय आपने "जनता का बजट जनता के द्वारा जनता लिए " बनाने का फैसला यदि वास्तव में किया है तो "योग अनुदेशक संगठन उत्तराखंड " की कुछ मांगें हैं उम्मीद है इन पर आपकी सरकार अवश्य ठोस निर्णय लेगी।

1 - हमें सम्मान जनक मानदेय दिया जाय, केंद्र सरकार हमें 250 रु दे रही है इसी तर्ज पर राज्य सरकार अगले वजट में योग अनुदेशकों के लिए कुछ बजट अवश्य रखे।

2 - सभी hwc में कार्यरत योग अनुदेशकों को भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन किया जाय।

3 - जब भी hwc में योग की परमानेंट भर्ती हो तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पहले से ही कार्यरत अनुदेशक को उसी जगह समायोजित किया जाय।

सर नमस्कार 🙏🙏 जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष मंत्रालय की आयुष्मान भारत मिशन योजना के तहत सभी वेलनेस हॉस्पिटल में योग अनुदेशक कार्यरत हैं, महोदय जिसमें महिला अनुदेशक को 250 रूपये प्रति सेशन के अनुसार पूरे महीने का अधिकतम 5000 रूपये दिया जा रहा है, एवं पुरुष अनुदेशक को 250 रूपये प्रति सेशन के अनुसार पूरे महीने में अधिकतम 8000 रूपये मानदेय दिया जा रहा है। महोदय आप स्❖

From : पहाड़ी भुला himanshu Agari
<himanshuagari9393@gmail.com>

Tue, Dec 26, 2023 03:03 PM

Subject : सर नमस्कार 🙏🙏 जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष मंत्रालय की आयुष्मान भारत मिशन योजना के तहत सभी वेलनेस हॉस्पिटल में योग अनुदेशक कार्यरत हैं, महोदय जिसमें महिला अनुदेशक को 250 रूपये प्रति सेशन के अनुसार पूरे महीने का अधिकतम 5000 रूपये दिया जा रहा है, एवं पुरुष अनुदेशक को 250 रूपये प्रति सेशन के अनुसार पूरे महीने में अधिकतम 8000 रूपये मानदेय दिया जा रहा है। महोदय आप स्❖

To : Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

योग अनुदेशक

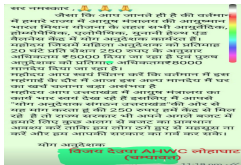
From : vijaydeopa61@gmail.com

Tue, Dec 26, 2023 06:15 AM

Subject : योग अनुदेशक

📎 1 attachment

To : Budget Department Gov. of Uttarakhand <Budget-uk@nic.in>



IMG_20231226_061210.jpg
711 KB

सर नमस्कार , 🙏 🙏 🙏

जैसा कि आप जानते ही है की वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष मंत्रालय की आयुष्मान भारत मिशन योजना के तहत सभी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, युनानी हेल्थ एंड वैलनेस केंद्र में योग अनुदेशक कार्यरत हैं। महोदय जिसमें महिला अनुदेशक को प्रतिमाह 20 घंटे प्रति सेशन 250 रुपए के अनुसार अधिकतम ₹5000 दिया जा रहा है एवं पुरुष अनुदेशक को प्रतिमाह अधिकतम ₹8000 मानदेय दिया जा रहा है।

महोदय आप स्वयं चिंतन करें कि वर्तमान में इस महंगाई के दौर में आज इस अल्प मानदेय में घर का खर्च चलाना बड़ा असंभव है

महोदय आप उत्तराखंड में आयुष मंत्रालय का कार्य भार स्वयं देख रहे हैं इसलिए मैं आपसे "योग अनुदेशक संगठन उत्तराखंड"की ओर से यह मांग करता हूं की 250 रुपए हमें केंद्र से मिल रहे है तो राज्य सरकार भी अपने अगले बजट में हमारे लिए कुछ अलग से बजट का प्रावधान अवश्य करें ताकि हम लोग ठगे हुए से महसूस ना करें और हम आपकी सरकार का गर्व कर सके।

योग अनुदेशक

**विजय देउपा AHWC लोहाघाट
(चम्पावत)**

A.H.W.C में कार्यरत योग अनुदेशको को सम्मान जनक वेतन , एवं भारतीय चिकित्सा परिषद में भी रजिस्ट्रेशन कराने हेतु।

From : dev raturi 3510 <dev.raturi.3510@gmail.com>

Mon, Dec 25, 2023 07:20 PM

Subject : A.H.W.C में कार्यरत योग अनुदेशको को सम्मान जनक वेतन , एवं भारतीय चिकित्सा परिषद में भी रजिस्ट्रेशन कराने हेतु।

To : Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

सर नमस्कार 🙏🙏

जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान मे हमारे राज्य मे आयुष मंत्रालय की आयुष्मान भारत मिशन योजना के तहत सभी आयुर्वेदिक, होमीयोपैथिक, एलापैथिक, यूनानी हेल्थ एन्ड वेलनेस हॉस्पिटल में योग अनुदेशक कार्यरत हैं, महोदय जिसमे महिला अनुदेशक को 250 रूपये प्रति सेशन के अनुसार पूरे महीने का अधिकतम 5000 रूपये दिया जा रहा है, एवं पुरुष अनुदेशक को 250 रूपये प्रति सेशन के अनुसार पूरे महीने में अधिकतम 8000 रूपये मानदेय दिया जा रहा है।

महोदय आप स्वयं चिंतन करें वर्तमान में एक फोर्थ क्लास कर्मचारी का वेतन भी 35000 के आसपास है, योग अनुदेशक की क्वालिफिकेशन after ग्रेजुएशन pg डिप्लोमा योग एवं ma योग है में पूछना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों किया गया है, महोदय इस बात का जबाब अवश्य दीजियेगा।

महोदय आप उत्तराखंड में आयुष मंत्रालय का कार्यभार स्वयं देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे "योग अनुदेशक संगठन उत्तराखंड " की ओर से यह मांग करता हूँ कि 250 रु हमें केंद्र से मिल रहे हैं तो राज्य सरकार भी अपने अगले वजट में हमारे लिए कुछ अलग से वजट का प्रावधान अवश्य करे ताकि हम लोग ठगे हुए से महसूस न करें और हम आपकी सरकार पर गर्व कर सकें।

महोदय यदि आप और आपकी सरकार वास्तव में योग के लिए कुछ करने का दावा करती हैं तो कृपया इन बिंदुओं पर अवश्य विचार करें।


महिला और पुरुष अनुदेशक का कार्य व वेतन भी समान हो, हमें भारतीय चिकित्सा परिषद में भी रजिस्ट्रेशन कराया जाय, एवं जब कभी योग में परमानेंट भर्ती हो तो जो अनुदेशक जहां पर भी कार्यरत है उसे वहीं पर समायोजित किया जाय, ऐसी मांग हमारे संगठन की है।

उम्मीद है इस पर भी अवश्य विचार किया जायेगा। 🙏🙏🙏🙏

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में योग अनुदेशकों हेतु बजट का प्रावधान

From : govindsingh4176@gmail.com

Mon, Dec 25, 2023 06:58 PM

Subject : आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में योग अनुदेशकों हेतु बजट का प्रावधान **To :** Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

उत्तराखंड सरकार से विनम्र अनुरोध है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो योग अनुदेशक लगे हुए हैं उन्हें मात्रा 5000,8000 रुपए में काम करना पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है कि बजट में योग अनुदेशकों ने मानदेय हेतु उचित बजट का प्रावधान किया जाय ताकि सभी योग अनुदेशक सम्मानजनक जीवन जी सकें। धन्यवाद

बर्ष 2024-25 के बजट हेतु सुझाव**From :** smbijalwandio@gmail.com

Mon, Dec 25, 2023 02:39 PM

Subject : बर्ष 2024-25 के बजट हेतु सुझाव**To :** budget uk gov in <budget.uk.gov.in@gmail.com>**Cc :** Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

- 1- राज्य सरकार के व्दारा वित्तीय बर्ष 24-25 के बजट आबंटन से पूर्व योजनाओ से लाभन्वित होने वाले क्षेत्र व जनता का आकलन भी किया जाय।
- 2- सुदूर ग्रामीण अंचलो में विधानसभा क्षेत्रवार ग्रामीण सडको के रखरखाव को पहली प्राथमिकता दी जाय,ताकि उत्तराखण्ड की जनता राज्य व राष्ट्रीय मोटर मार्गो तक पहुंचने मे सुविधा हो।
- 3- पर्वतीय ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रो की स्वास्थ सेवाओ को सुदृढ बनाने की दिशा में संसाधन व कुशल कर्मियो की तैनाती की दिशा मे उचित वजट व क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाय। ताकि ग्रामीण क्षेत्रो की गर्भवती मां बहिन बेटियो की जिन्दगी संकट में न पडे।
- 4-पर्वतीय जनपदो के विभिन्न माध्यमिक,व उच्च शिक्षण संस्थानो मेंरिक्त पदो पर नियुक्तियां,भवन,अन्य पाठन सामग्री संसाधनो हेतु पर्याप्त वजट की व्यवस्था हो।
- 5-भाजपा की पूर्व सरकारो ने जिन नये जनपदो की स्थापना हेतु शासनादेश जारी किये थे,उन्हें शीघ्र स्थापित करने व संसाधनो हेतु पर्याप्त वजट की व्यवस्था की जाय।
- 6- सरकार व्दारा चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के साथ ही अधूरे कार्यों हेतु वजट की व्यवस्था की जाय।
- 7- पर्वतीय क्षेत्रो में उपलब्ध कच्चे माल का संज्ञान हेतु ब्लॉक मुख्यालयो अथवा जिला मुख्यालयो पर ऐसे केन्द्र बनाये जायं ,जहां कच्चे माल संग्रहण,निर्माण,व विपणन की व्यवस्था एक जगह हो,उसके लिये बजट की व्यवस्था हो,ताकि स्थानीय युवाओ को अपने घर आसपास रोजगार मिल सके,और पालायन पर रोक लग सके।
- 8- पहाडी जनपदो के ऐसे क्षेत्र जहां बर्षा के कारण आवागमन नदी नालो के कारण प्रभावित होते है,वहां स्थायी रूप से पुल,या फलाई ओवर बनाये जायं।इसमें भी बजट की व्यवस्था की जाय।
- 9- कृषि व उद्यान, पशुपालन से जुडे कास्तकारो को विपणन की सुविधा के ही अन्य सुविधाओ पर भी ध्यान दिया जाय।
- 10- आपदो से निपटने हेतु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रो में मिनी स्टेडियम बनाये जायं,जो दुर्घटनाओ,आपदो हैलीसेवाओ के लिये भी सुलभ हो सकते है।

एस एम बिजल्वान,
सेवानिवृत सूचनाधिकारी,टिहरी।

बजट 2024-25 की निर्माण प्रक्रिया हेतु सुझाव

From : subhenduparashar@gmail.com

Mon, Dec 25, 2023 02:37 PM

Subject : बजट 2024-25 की निर्माण प्रक्रिया हेतु सुझाव



To : Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी
देहरादून, उत्तराखंड
सादर अभिवादन,

2024-25 के बजट निर्माण में जनता से मांगे गए सुझाव हेतु, आपका बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में विगत वर्षों की बजट निर्माण प्रक्रिया बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय रही है, क्योंकि विगत सभी बजट जीवन तथा प्रकृति के सभी पहलुओं को समाहित करने वाले रहे हैं, इसी परिपेक्ष 2024-25 बजट हेतु मेरे निम्न सुझाव प्रासंगिक हैं-

- 1) हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, यहां की नैसर्गिक सुंदरता तथा प्रकृति को उसके स्वाभाविक स्वरूप व शाश्वतता को उसके पौराणिकता के अनुरूप अक्षुण्ण रखा जा सके, इस हेतु प्रावधान...।
- 2) infrastructure हेतु जो बजट हो, वह इस प्रकार हो कि वह हमारी कृषि योग्य भूमि को उसर अथवा बंजर न बनाएं तथा हमारे जल के सभी स्रोतों की पवित्रता को कायम रख सके, आज हम जगह-जगह देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी ज्यादातर नहरों के जल विषैले तथा काले रंग के हो गए हैं जो कि हमारी फसलों के सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं है।
- 3) प्राकृतिक स्रोतों के अनावश्यक दोहन तथा उसके दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रावधान..।
- 4) मानव द्वारा छोड़े गए पशुओं तथा अन्य आवारा पशुओं की रक्षा हेतु प्रावधान ...।
- 5) निजी संस्थान में कार्य कर रहे युवाओं तथा युवतियों के साथ हो रहे शोषण हेतु प्रावधान ।

विशेष-माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी राज्यवासियों के हितार्थ 'उत्तराखंड' को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है, इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान एक और विशेष विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं- राज्य में निवास करने वाली सभी युवा शक्ति, वह चाहे ग्राम, नगर, ब्लॉक, तहसील, जिला जहां कहीं भी रह रही हो, इनमें से जो लोग उद्देश्य पूर्ण सार्थक जीवन यापन कर रहे हैं अथवा अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है इन्हें छोड़कर ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो कुछ श्रेष्ठ करना तो चाहते हैं, परंतु किसी अभाव अथवा दिशाहीनता के कारण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है यह लोग अल्प शिक्षित हो या शिक्षित हो पर जो कुछ भी हो कहीं न कहीं यह राज्य की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकने की स्थिति में नहीं है, इनकी ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों में ना लगे, इनका जीवन सार्थक हो सके, इस दिशा में यदि कोई कार्य किया जा सके या इसके लिए कोई प्रावधान बनाया जा सके जो की ग्राम स्तर से शुरू होकर जिला स्तर तक कार्य करें तो मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश को श्रेष्ठतम प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।

आपका भाई
शुभेन्दु पाराशर पाण्डेय
ग्राम रामनगर (रुद्रपुर)
जिला-उधम सिंह नगर
उत्तराखंड
फोन नंबर-9412969775
subhenduparashar@gmail.com

Photo from बजट स्वीकृत हेतु अनुरोध पत्र

From : javedalirke9760@gmail.com

Sat, Dec 23, 2023 11:58 PM

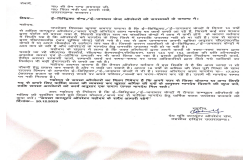
Subject : Photo from बजट स्वीकृत हेतु अनुरोध पत्र



To : Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

1 attachment

Cc : ali25407@gmail.com



IMG-20231221-WA0014.jpg
219 KB

सेवामें,

मा० श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल जी,
मा० वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री,
उत्तराखण्ड सरकार।

विषय:— ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्र/ई-जनाधार केन्द्र ऑपरेटरों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट/ई-जनाधार केन्द्रों में विगत 10 वर्षों से अधिक कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अल्प मानदेय पर कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें कई बार शासन द्वारा पोर्टल को बदला गया है, जिससे तहसील स्तर पर संचालित केन्द्रों में आय में कमी होने के कारण वर्तमान में स्थिति यह है कि ऑपरेटरों को मानदेय के लिए जिले में धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जब से शासन द्वारा सी०एस०सी० (जन सुविधा केन्द्र) खोले गये हैं। तब से आम जनमानस अपनी सुविधा अनुसार सी०एस०सी० केन्द्रों में या अपने मोबाईल से आवेदन कर रहा है। जिसके कारण तहसीलों के ई-डिस्ट्रिक्ट/ई-जनाधार केन्द्रों में आय कम हो रही है और ऑपरेटरों के मानदेय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

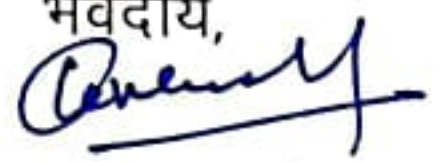
महोदय के संज्ञान में लाना है कि उक्त ऑपरेटरों द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ शासन द्वारा चलाये जा रहे सी०एम० डैशबोर्ड, सी०एम० हेल्पलाईन, सीपी०ग्राम, धारा 143 एवं 154 आदेश की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना एवं ई-ऑफिस प्रणाली पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन सम्बन्धी कार्य, दैवीय आपदा सम्बन्धी कार्य, सम्बन्धी कार्य एवं समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये दायित्वों का निर्वाहन भी बड़ी ईमानदारी से करते आ रहे हैं।

महोदय अवगत कराना है कि तैनात ऑपरेटर वर्तमान में इस स्थिति में हैं कि अन्य जगह न तो नौकरी हेतु प्रयास कर सकते हैं और न कही जा सकते हैं। अपना 10 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी निष्ठा के साथ राजस्व विभाग के अन्तर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट/ई-जनाधार केन्द्रों में दी है। समस्त ऑपरेटर अल्प मानदेय रू- 17,670 (सत्तरह हजार छ सौ सत्तर) रूपये पर अपने परिवार/बच्चों का भरण-पोषण कर रहे हैं। उसमें भी मानदेय समय पर नहीं मिलता है।

महोदय से समस्त ऑपरेटरों का विन्नम निवेदन है कि अपने स्तर से जिला योजना या अन्य किसी मद से हमारे लिए वार्षिक बजट की व्यवस्था कर कुशल श्रमिक की दरों के अनुसार मानदेय दिलाने की कृपा करें, ताकि समस्त ऑपरेटरों को कार्य अनुसार एक समान जनक मानदेय मिल सके।

अतः महोदय से निवेदन है कि ई-डिस्ट्रिक्ट/ई-जनाधार केन्द्रों में तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटरों के भविष्य को सुरक्षित करते हुये जिला योजना/अन्य मद से मासिक मानदेय हेतु वार्षिक बजट उपलब्ध करवाने की कृपा करें। "समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटर महोदय के सदैव आभारी रहेंगे"

दिनांक:— 20.12.2023

भवदीय,


देव भूमि कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ,
तहसील हरिद्वार उत्तराखण्ड।

Suggestion for the Devbhoomi upcoming budget Development.

From : gamit5495@gmail.com

Fri, Dec 22, 2023 08:07 AM

Subject : Suggestion for the Devbhoomi upcoming budget Development.**To :** Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

Respected Sir,

Greetings!

I have seen this article in the daily newspaper where the department is looking for feedback from the citizens of Uttarakhand and being a proud citizen I would to share my feedback with this email on the upcoming budget it might help in planning the development schemes for Devbhoomi welfare, below are my recommendations please refer to the below:

1. Uttarakhand has amazing potential for tourism, but it's limited to only a few places because some districts lack opportunities and development. We should focus on developing **lesser-known villages like Bironkhal in Pauri district and other villages in Uttarkashi all**. Promoting these places and training locals in new skills can create unique businesses and make these areas popular for tourists.
2. Dehradun in Uttarakhand has become a major education hub, attracting many people from other districts. We can use this by supporting research centers, and labs, and organizing study tours to undiscovered places in Uttarakhand. This not only benefits locals but also helps improve technology and connectivity.
3. With more people moving to urban areas in Uttarakhand, many mountain villages are becoming empty due to a lack of opportunities and services. We should focus on **bringing IT industries to the hills and encourage companies to set up internet or satellite Wi-Fi. This can improve Uttarakhand's situation without harming its natural beauty**. Companies setting up offices in peaceful villages could also support their employees' mental well-being and healthy lifestyles in a pure and serene environment.
4. **Promoting and building underground offices to prevent cutting down trees and deforestation.**
5. **Using air services to sprinkle flower seeds during the rainy season when villagers avoid sending their cattle to the mountains. This helps nature take care of the necessary requirements for plant growth, reviving the barren mountains and bringing life to Uttarakhand.**
6. **Employing creative methods to showcase the local culture and increasing the availability of organic food and products from Uttarakhand. This involves supporting businesses and local organizations to boost the supply of organic items.**

I believe that my suggestion will be incorporated in the upcoming FY budget, and I will be happy if I can incorporate more suggestions. Looking for your positive response.

बजट सुझाव

From : hsinghdhundhara@gmail.com

Thu, Dec 21, 2023 11:32 AM

Subject : बजट सुझाव**To :** Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

उत्तराखंड को समृद्ध बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापना करने के लिए अप्रुवल प्रक्रिया एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को आसान एवं त्वरित किया जाये। पलायन रोकने में मददगार लघु उद्योग स्थापित करने में सहायक उद्यमियों, ग्रामीणों एवं प्रधानों को सम्मानित किया जाये। ग्रामीण सड़कें पक्की बनाई जाये। गांवों को उपज आधारित मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने को प्रोत्साहित किया जाये। प्रशासन आपके द्वार दस्तावेज आवेदन से लेकर पूरी प्रक्रिया कर उसी दिन आवेदक को तैयार कर दिया जाना सुनिश्चित करें। राज्य में नवाचार एवं जोखिम भरे नवीन उद्योग स्थापित करने पर उत्पादन शुरू करने में सरकार सहायक बने। रिमोट गांवों में अनिवार्य रूप से डाक्टर, दवाखाने, अध्यापक, वेटनरी डाक्टर, आवश्यक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं और नशामुक्ति काउंसलिंग व्यवस्था प्रदान कर दीर्घकालिक विकास किया जा सकता है। पहाड़ों के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए प्यर्टकों एवं यात्री जनों को प्लास्टिक फ्री यात्रा के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया जाये। यात्री जनों को उत्तराखंड के लोगों द्वारा विशिष्ट स्नेह एवं उच्च गुणवत्ता पूर्ण सुविधाएं राज्य के उज्ज्वल भविष्य का आधार साबित हो इसके लिए मेहमाननवाजी के मापदंड निर्धारित किया जाये।

हरफूल सिंह

शिक्षा के सम्बन्ध में

From : shadabmalik888@gmail.com

Thu, Dec 21, 2023 08:59 AM

Subject : शिक्षा के सम्बन्ध में

To : Budget Department Gov. of Uttarakhand <budget-uk@nic.in>

बजट में शिक्षा का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए.
शिक्षा का सबसे ज़्यादा बुरा हाल गाँवों का है.
डिग्री कॉलेज दूर होने के कारण हमारी यहाँ की महिलायें शिक्षा से वंचित रह रही हैं.

--

Malik malik

S.No.	Name	Email	Department	Date	Comment
1	Kamal Pandey	Doweknow50@gmail.com	Accountant General Office	2024-01-07 18:25:10	Respected Sir, I request you to please make provision for transfer rule in this tear budget 2024. CM sir when we join in Uttrakhand state service then we can not transfer from one district to another. We can transfer only by mutual transfer but by this we will loose seniority. There are many employees in state government who want to go to their home district but due to transfer rule they cannot get transfer. Chief Minister sir, please include provisions for transfer without loosing seniority.
2	JAVED ALI	JAVEDALI25407@GMAIL.COM	Department of Revenue	2023-12-27 11:07:06	मा0 मंत्री जी उत्तरखण्ड सरकार देहरादून महोदय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों द्वारा अनुरोध करता हूँ कि महोदय प्रदेश में बजट की सुविधाये लागू होनी चाहीये जिससे कर्मचारी को हर महीने बजट मिला रहे है
3	sanjeev chauhan	Chauhan.sanjeev22@gmail.com	Agriculture Department	2023-12-23 21:29:35	mahody ji uttrakhand me sabse adhik sambhawnaye krishi me hi h iske liye aapko jamini sthar par ja kar alag alg jagh ke liye alag alg yojna bana kar kary karna hoga aur ho sake to jis bhumi par bhi ho sake sarkar kirsdhi karwa de
4	Navjeet Singh Rawat	bobyrawat2345@gmail.com	Accountant General Office	2023-12-23 07:39:18	Firstly, thanks to the state government and the department for this opportunity, and I will say in favour of tourism. Like Tehri, we have to focus more on small towns and villages to increase tourism and to increase employment in those areas, like I am from Pauri Garhwal, so Thailisain, Satpuli, Bilkhet, and many more attractive places are there, so please make some policies in favour of this and explain why Satpuli's lake project is delaying.
5	Dr Pankaj Bijalwan	pankajbijalwan@gmail.com	Dehradun - Uttarakhand	2023-12-22 13:07:36	on entry of vehicle of other states ecotax may be levied.

6	Suraj	sk1369302@gmail.com	Accountant General Office	2023-12-21 18:35:18	बाल कल्याण हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना एक अत्यंत सराहनीय कार्य है। मेरा सुझाव है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की अवधि को बढ़ाकर अभिभावक की मृत्यु की तिथि से की जानी चाहिए। ताकि निराश्रित बच्चों को सहायता मिल सके।।
7	sunil	sunildhaundiya@gmail.com	Welfare of Scheduled Caste , Schedule Tribes and Other Backward Classes	2023-12-21 16:29:40	वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण, जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला कल्याण तथा विकलांग कल्याण संचालित किये जा रहे हैं। उक्त के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग एवं महिला आयोग जैसे कार्यालय खोले गये हैं। राज्य हित में उचित होगा कि उक्त सभी कार्यालयों को प्रदेश मुख्यालय पर खोलते हुए सभी कार्यालयों एवं आयोगों का एकीकरण कर दिया जायें ताकि राज्य का वित्तीय भार कम किया जा सके।
8	NIKUNJ AGARWAL	nikunj95agarwal@gmail.com	Dehradun - Uttarakhand	2023-12-21 15:07:12	More Flyovers & Underpass , with continuation Of Smart City Development, smart Lights, beautification Work Continuation. Make Dehradun a destination!
9	Bhanu	devbhoomikelog001@gmail.com	State Finance Commission	2023-12-21 13:35:30	Making provision of a Research and Development Wing in each department of state govt. It should be done to adopt new techniques, reduce time, increase efficiency of delivery, easy to use for public, cost cutting & saving time and resources for the dept. We see a lot of budget is being wasted in routine works which can be saved and avoided by adopting new techniques. A small R&D segment will make extremely significant differences.

10	Bhanu	Devbhoomikelo g001@gmail.com	Uttarakhand Public Service Commission	2023-12-21 13:29:56	The exam pattern of exams undertaken by UKPSC & UKSSSC needs to be updated and modified as per present day requirements. It should be an overall knowledge test with various aspects. Science and scientific temper must be tested rather than facts that require only rote learning and mugging up. Hindi is irrelevant nowadays, usable and out of the box questions that make people to think, test thinking ability must be framed.
11	Rajeev negi	rajeevnegiacc@ gmail.com	Accountant General Office	2023-12-21 08:59:16	Please increase budget for education and stop spending money on half baked policies like atal utkrisht vidhyalay we do not have enough teachers in the schools, primary schools are working on a single teacher, how can a single teacher teach students from class 1 to 5 ? Our state can only improve if we provide quality education to our children, we are the first state in Himalayan states to implement NEP, please don't let it go to waste